रोमेश थापर

बनाम

मद्रास राज्य

[श्री हरिलाल कानिया सी.जे., सैय्यद फजल अली, पतंजलि शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और डीएएस, न्यायमूर्तिगण]

भारत का संविधान, अनुच्छेद 19, अन्यथा (1) (ए) और (2), 32-अनुच्छेद के तहत आवेदन। 32-प्रारंभिक आपत्ति-सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने और सार्वजनिक सुरक्षा बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाने वाली भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार-वैधता-अधिनियम की पृथक्करणीयता-मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम (1949 का XXXIII), एस। 9 (1-ए)-वैधता.

पूर्ण न्यायालय द्वारा माना गया (i) (प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज करते हुए) -संविधान के तहत सर्वोच्च न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर माना जाता है, और यह अपने ऊपर दी गई जिम्मेदारी के अनुरूप आवेदनों पर विचार करने से इनकार नहीं कर सकता है। ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सुरक्षा। हालाँकि इस तरह के आवेदन पहली बार में मामले में समवर्ती क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय का सहारा लिए बिना न्यायालय में किए जाते हैं।

*उर्गुहार बनाम ब्राउन (205 यू.एस. 179.) और हूनी बनाम कोलोहन (*294 यू.एस. 103) प्रतिष्ठित हैं।

ii) भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है और यह स्वतंत्रता प्रसार की स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है।

एकपक्षीय जैक्सन (96 यू.एस. 727) और लवेल बनाम सिटी ऑफ ग्रिफिन (303 यू.एस. 444) का उल्लेख किया गया है।

कानिया सी.जे., पतंजलि.आई. शास्त्री, मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और डीएएस आईजे.-(एफएजेडएल अली जे. असहमति) के अनुसारअभिनिर्धारित: (i) मानहानि, बदनामी आदि के अलावा, जब तक कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून पूरी तरह से निर्देशित न हो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने या उसे उखाड़ फेंकने के खिलाफ, ऐसा कानून सीएल के तहत आरक्षण के दायरे में नहीं आ सकता। (2) कला का. संविधान के अनुच्छेद 19 में, हालाँकि जिन प्रतिबंधों को वह लागू करना चाहता है, उनकी कल्पना आम तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में की गई होगी। 1949 के मद्रास मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर एक्ट, XXXII की धारा 9 0-ए), जो सार्वजनिक सुरक्षा हासिल करने के व्यापक उद्देश्य के लिए प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करती है या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव को सीएल के तहत अधिकृत प्रतिबंधों के दायरे से बाहर करती है। (2) और इसलिए शून्य और असंवैधानिक है; (ii) जहां एक कानून किसी मौलिक अधिकार पर इतने व्यापक स्तर

पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करता है कि वह ऐसे अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से स्वीकार्य विधायी कार्रवाई की सीमा के भीतर और बाहर दोनों तरह के प्रतिबंधों को कवर कर सके, तो यहां तक कि इसे बरकरार रखना भी संभव नहीं है। इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर लागू किया जा सकता है, क्योंकि यह अलग करने योग्य नहीं है। जब तक संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए इसके लागू होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, तब तक इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य माना जाना चाहिए। इसलिए धारा 9 (1-ए) पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य है।

प्रति *फजल* अली जे.-प्रतिबंध जो धारा 9 (1-ए) द्वारा अधिकृत हैं, कला के सीएल (2) के प्रावधानों के भीतर हैं। संविधान के 19 और धारा. इसलिए 9(1-ए) असंवैधानिक या शून्य नहीं है। (1)

बृज भुज्झन और अन्य बनाम राज्य (1950) एस.सी.आर. 60) का उल्लेख किया गया है। .

मूल क्षेत्राधिकार: याचिका संख्या XVI, 1950, संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत निषेध और उत्प्रेषण रिट के लिए आवेदन। फैसले में तथ्य सामने रखे गए हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से सी. आर. पट्टाभि रा1नान।

विपरीत पक्ष की ओर से मद्रास के एडवोकेट जनरल के. राजा अय्यर (गणपति अय्यर, उनके साथ)।

1950. 26 मई. कानिया सी.जे., मेहर चंद महाजन, मुखर्जी और दास न्यायमूर्ति/न्यायमूर्तिगण, का निर्णय। पतंजलि शास्त्री द्वारा दिया गया था, जे. फज़ल अली जे. ने एक अलग निर्णय दिया।

याचिकाकर्ता पतंजलि शास्त्री जे. क्रॉस नामक अंग्रेजी में हाल ही में शुरू हुई साप्ताहिक पत्रिका के मुद्रक, प्रकाशक और संपादक हैं। रोड्स बंबई में मुद्रित और प्रकाशित। मद्रास सरकार, यहां प्रतिवादी, ने मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 (इसके बाद विवादित अधिनियम के रूप में संदर्भित) की धारा 9(1-ए) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक आदेश संख्या एमएस 1333 जारी किया। 1 मार्च, 1950 को उन्होंने उस राज्य में पत्रिका के प्रवेश और प्रसार पर प्रतिबंध लगा दिया। आदेश फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में प्रकाशित किया गया था और अधिसूचना इस प्रकार थी:-

"मद्रास सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव अधिनियम, 1949 (मद्रास अधिनियम XXIII, 1949) की धारा 9 (1-ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मद्रास के महामहिम राज्यपाल, जनता को सुरक्षित करने के उद्देश्य से संतुष्ट हैं सुरक्षा और सार्वजनिक

व्यवस्था के रखरखाव के लिए, ऐसा करना आवश्यक है, इसके द्वारा, फोर्ट सेंट जॉर्ज गजट में इस आदेश के प्रकाशन की तारीख से, इसमें प्रवेश या संचलन, बिक्री या वितरण पर रोक लगा दी गई है। मद्रास राज्य या बॉम्बे में प्रकाशित अंग्रेजी साप्ताहिक क्रॉस रोड्स नामक समाचार पत्र का कोई भाग।"

याचिकाकर्ता का दावा है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार (1) ब्रिज भूषण बनाम द स्टेल ऑफ दिल्ली, पृष्ठ 605 इन्फ्रा.स्पीच और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है जो उसे अनुच्छेद 19 (1) (ए) द्वारा प्रदत्त है।) संविधान का और वह विवादित अधिनियम की धारा 9 (1-ए) की वैधता को संविधान के अनुच्छेद 13 (1) के तहत शून्य होने के रूप में चुनौती देता है क्योंकि यह उसके पूर्वोक्त मौलिक अधिकार के साथ असंगत है।

उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित मद्रास के महाधिवक्ता ने प्रारंभिक आपत्ति उठाई, वास्तव में अनुच्छेद 32 के तहत आवेदन पर विचार करने के लिए इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर नहीं, बल्कि पहली बार में ऐसी राहत के लिए सीधे इस न्यायालय का सहारा लेने वाले याचिकाकर्ता पर। उन्होंने तर्क दिया कि, व्यवस्थित प्रक्रिया के तहत, याचिकाकर्ता को पहले मद्रास उच्च न्यायालय का सहारा लेना चाहिए, जिसके पास संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत मामले से निपटने के लिए समवर्ती क्षेत्राधिकार है। उन्होंने आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 435 के तहत आपराधिक पुनरीक्षण याचिकाओं, जमानत के लिए आवेदन और नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24 के तहत स्थानांतरण के लिए आवेदनों का हवाला दिया, जहां कुछ मामलों में उच्च न्यायालय और एक न्यायालय को समवर्ती क्षेत्राधिकार दिया गया है। निचली श्रेणी में, अभ्यास का एक नियम स्थापित किया गया है कि एक पक्ष को उच्च न्यायालय का सहारा लेने से पहले राहत के लिए पहले बाद वाले न्यायालय में जाना चाहिए। उन्होंने सम्राट बनाम बिशेषन जार प्रसाद सिन्हा(1) का उल्लेख किया जहां एक आपराधिक मामले में अभ्यास का ऐसा नियम लागू किया गया था, और हमारा ध्यान कुछ अमेरिकी निर्णयों उर्कहार्ट बनाम ब्राउन(') और हूनी बनाम कोलोहन(') की ओर भी आकर्षित किया। यह दर्शाता है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय को आम तौर पर आवश्यकता होती है• कि संघीय में आवेदक के लिए जो भी न्यायिक उपचार खुले रहें। सभी राज्य न्यायालयों को सर्वोच्च न्यायालय में उपाय से पहले थक जाना चाहिए - चाहे वह बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या सर्टिओरारी की अनुमति दी जाएगी। हमारी राय है कि न तो विद्वान महाधिवक्ता द्वारा उल्लिखित उदाहरण और न ही उनके द्वारा संदर्भित अमेरिकी निर्णय वास्तव में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 द्वारा दिए गए उपाय के अनुरूप हैं। वह अनुच्छेद केवल इस न्यायालय को, जैसा कि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालयों को देता है, भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के लिए या

किसी अन्य उद्देश्य के लिए, अपने सामान्य क्षेत्राधिकार के हिस्से के रूप में, कुछ रिट जारी करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। उस स्थिति में इसे अनुच्छेद 131 से 139 के बीच अधिक उचित रूप से रखा जाता जो उस क्षेत्राधिकार को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 32 उन अधिकारों के प्रवर्तन के लिए एक "गारंटीयुक्त" उपाय प्रदान करता है, और इस उपचारात्मक अधिकार को भाग यूएल में शामिल करके एक मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इस प्रकार इस न्यायालय को मौलिक अधिकारों का रक्षक और गारंटर माना जाता है, और यह लगातार ऐसा नहीं कर सकता है। इस प्रकार की ज़िम्मेदारी, ऐसे अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ सुरक्षा की मांग करने वाले आवेदनों पर विचार करने से इंकार कर देती है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं पाया जाता है और हम नहीं मानते कि अमेरिकी निर्णय सही हैं।

अब गुणों की ओर मुड़ते हुए, इसमें कोई संदेह नहीं है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में विचारों के प्रचार-प्रसार की स्वतंत्रता शामिल है, और यह स्वतंत्रता प्रसार की स्वतंत्रता से सुनिश्चित होती है। "परिसंचारण की स्वतंत्रता मेरे लिए एक सबक है कि स्वतंत्रता प्रकाशन की स्वतंत्रता है। वास्तव में, प्रसार के बिना प्रकाशन का कोई महत्व नहीं होगा।" एकपक्षीय जैक्सन (1)सेक लोवेल बनाम सिटी ऑफ ग्रिफिन (2) इसलिए यह पूरी तरह से स्पष्ट है कि मद्रास सरकार का आदेश अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जब तक कि विवादित अधिनियम की धारा 9 (आईए) जिसके तहत इसे बनाया गया था, अनुच्छेद 19 के खंड (2) में उल्लिखित आरक्षणों से बचाई गई है, जो (अपमान, निंदा इत्यादि से संबंधित कानूनों के संबंध में सारहीन शब्दों को छोड़ देती है, जिनके साथ हमारा कोई संबंध नहीं है) इस मामले में) किसी भी "मौजूदा कानून के संचालन को बचाता है जहां तक यह किसी ऐसे मामले से संबंधित है जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है, या उसे उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है।" तदनुसार प्रश्न उठता है कि क्या विवादित अधिनियम, जहां तक इसका उद्देश्य है: धारा 9(1-ए) द्वारा प्रांतीय सरकार को "सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से" अधिकृत करना है। मद्रास प्रांत या उसके किसी भाग में किसी दस्तावेज़ या दस्तावेज़ों के वर्ग में प्रवेश या संचलन, बिक्री या वितरण को प्रतिबंधित या विनियमित करना "किसी भी मामले से संबंधित कानून है जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है या उखाड़ फेंकने की प्रवृत्ति रखता है। "

भारत सरकार अधिनियम, 1935 की धारा 100 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, उस अधिनियम की सातवीं अनुसूची की सूची II की प्रविष्टि I के साथ पठित, जिसमें अन्य मामले भी शामिल हैं, प्रांतीय विधानमंडल द्वारा पारित अधिनियम पारित

किया गया था। "सार्वजनिक व्यवस्था।" अब "सार्वजनिक व्यवस्था" व्यापक अर्थ की अभिव्यक्ति है और उस शांति की स्थिति का प्रतीक है जो राजनीतिक समाज के सदस्यों के बीच सरकार द्वारा लागू आंतरिक नियमों के परिणामस्वरूप प्रचलित होती है, जिसे उन्होंने स्थापित किया है। हालाँकि धारा 9 (1-ए) "सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने" और "सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव" को अलग-अलग उद्देश्यों के रूप में संदर्भित करती है, लेकिन यह माना जाना चाहिए कि "सार्वजनिक सुरक्षा" का उपयोग सार्वजनिक व्यवस्था की व्यापक अवधारणा के एक भाग के रूप में किया जाता है, क्योंकि, यदि सार्वजनिक सुरक्षा का उद्देश्य "सार्वजनिक व्यवस्था" अभिव्यक्ति की सामग्री से अलग और बाहर किसी भी मामले को इंगित करना होता, तो यह मद्रास विधानमंडल के लिए प्रावधान को अधिनियमित करने के लिए सक्षम नहीं होता, जहां तक यह सार्वजनिक सुरक्षा से संबंधित है। यह वास्तव में उत्तरदाताओं की ओर से विवादित नहीं था। लेकिन यह आग्रह किया गया कि विवादित अधिनियम में अभिव्यक्ति "सार्वजनिक सुरक्षा", जो कानून और व्यवस्था से संबंधित एक क़ानून है, का अर्थ प्रांत की सुरक्षा है, और इसलिए, "राज्य की सुरक्षा" के अर्थ में अनुच्छेद 19 (2) में "राज्य" को अनुच्छेद 12 में परिभाषित किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा, पूर्ववर्ती प्रांतों में से प्रत्येक की सरकार और विधानमंडल शामिल हैं। रेक्स बनाम वर्मवुड स्क्रब्स जेल(') पर इस दृष्टिकोण के समर्थन में बहुत अधिक निर्भरता रखी गई थी, जहां यह माना गया था कि रक्षा की धारा 1 में वाक्यांश "जनता की सुरक्षा के लिए, सुरक्षा और क्षेत्र की रक्षा" क्षेत्र (समेकन) अधिनियम, 1914, किसी विदेशी दुश्मन के खिलाफ देश को सुरक्षित करने तक ही सीमित नहीं था, बल्कि इसमें विद्रोह जैसी आंतरिक अव्यवस्था के खिलाफ सुरक्षा भी शामिल थी। यह निर्णय उत्तरदाताओं के लिए बहुत मददगार नहीं है क्योंकि जिस संदर्भ में उस अधिनियम में "सार्वजनिक सुरक्षा" शब्द आए थे, उससे स्पष्ट रूप से पता चलता है कि राज्य की सुरक्षा ही उद्देश्य था। हमारा ध्यान "सार्वजनिक सुरक्षा" अभिव्यक्ति की किसी भी परिभाषा की ओर आकर्षित नहीं हुआ है और न ही ऐसा प्रतीत होता है कि इन शब्दों ने कला के शब्दों के रूप में कोई तकनीकी अर्थ प्राप्त कर लिया है।

"सार्वजनिक सुरक्षा" का सामान्य अर्थ जनता की सुरक्षा या खतरे से उनकी मुक्ति है। उस अर्थ में, जो कुछ भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के खतरों को रोकता है उसे सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने वाला भी माना जा सकता है। हालाँकि, अभिव्यक्ति का अर्थ संदर्भ के अनुसार भिन्न होना चाहिए। उदाहरण के लिए, भारतीय दंड संहिता में अपराधों के वर्गीकरण में, अध्याय XIV में "सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, सुविधा, शालीनता और नैतिकता को प्रभावित करने वाले अपराध" की गणना की गई है और इसमें लापरवाही से गाड़ी चलाना या सार्वजनिक रास्ते पर सवारी करना (धारा 279) और शामिल है।

किसी जहाज का जल्दबाजी में नेविगेशन (धारा 280), अन्य बातों के अलावा, सार्वजनिक सुरक्षा के खिलाफ अपराध है, जबकि अध्याय VI में रानी के खिलाफ युद्ध छेड़ना (धारा 121), राजद्रोह (धारा 124-ए) आदि को "राज्य के खिलाफ अपराध" के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। क्योंकि उनकी गणना राज्य और अध्याय की सुरक्षा को कमजोर करने या प्रभावित करने के लिए की जाती है। VIII "सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध" को परिभाषित करता है जिसमें गैरकानूनी सभा (धारा 141) दंगा (धारा 146), वर्गों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना (धारा 153-ए), झगड़ा (धारा 159) आदि शामिल हैं। कानून और व्यवस्था "सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा" में सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा शामिल नहीं हो सकती है, इसका मतलब सार्वजनिक रास्ते पर लापरवाही से गाड़ी चलाने आदि के खिलाफ जनता को सुरक्षित करना हो सकता है, और जरूरी नहीं कि राज्य की सुरक्षा भी हो। यह कहा गया था कि एक अधिनियम जो निवारक हिरासत और समाचार पत्रों पर प्रतिबंध जैसे कठोर उपायों का प्रावधान करता है, उसे लापरवाही से गाड़ी चलाने या झगड़े जैसे मामूली अपराधों के बजाय राज्य की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले मामलों से संबंधित माना जाना चाहिए। लेकिन विवादित अधिनियम का जो भी अंत हो, उसे पूरा करने का इरादा रहा हो, और इसके निर्माताओं के जो भी लक्ष्य रहे हों, इसका आवेदन और दायरा, क़ानून में सीमित शब्दों के अभाव में, पूर्वाग्रहपूर्ण गतिविधि के उन गंभीर रूपों तक ही सीमित नहीं हो सकता है। जो राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने के लिए गणना की जाती है। न ही इस बात की कोई गारंटी है कि जो लोग अधिनियम के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हैं, वे उनका उपयोग करते समय उन लोगों के बीच भेदभाव करेंगे जो राज्य की सुरक्षा के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य करते हैं और जो ऐसा नहीं करते हैं।

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में कहीं भी "राज्य की सुरक्षा" अभिव्यक्ति का उपयोग नहीं किया गया है, हालांकि इसने सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से हिंसा के अपराधों से निपटने के लिए धारा 57 के तहत प्रावधान किया है। जबकि सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव सहित कानून और व्यवस्था का प्रशासन लोगों द्वारा चुने गए मंत्री को सौंपा गया था, राज्यपाल को उन व्यक्तियों के संचालन से निपटने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी जिन्होंने "प्रांत की शांति या शांति को खतरे में डाला था"। "सरकार को उखाड़ फेंकने के इरादे से हिंसा के अपराध" करना या करने का प्रयास करना। इसी तरह, संविधान का अनुच्छेद 352 राष्ट्रपति को आपातकाल की उद्घोषणा करने का अधिकार देता है जब वह संतुष्ट हो जाता है कि "भारत या क्षेत्र के किसी भी हिस्से की सुरक्षा इसका खतरा युद्ध या बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति से है।" ये प्रावधान मानते हैं कि सार्वजनिक शांति या अमन-चैन में अशांति इतना गंभीर रूप धारण कर सकती है कि राज्य की सुरक्षा को खतरा हो सकता है।

जैसा कि स्टीफन ने अपने इंग्लैंड के आपराधिक कानून (1) में कहा है: "गैरकानूनी सभा, दंगे, विद्रोह, विद्रोह, युद्ध लगाना, ऐसे अपराध हैं जो एक-दूसरे से टकराते हैं और पूरी तरह से परिभाषित सीमाओं द्वारा चिह्नित होने में सक्षम नहीं हैं। ये सभी आम तौर पर एक विशेषता यह है कि एक सभ्य समाज की सामान्य शांति उल्लिखित प्रत्येक मामले में या तो वास्तविक बल से या कम से कम उसके दिखावे और धमकी से परेशान होती है।" हालाँकि इन सभी अपराधों में सार्वजनिक शांति की गड़बड़ी शामिल है और ये सैद्धांतिक रूप से सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ अपराध हैं, उनके बीच का अंतर केवल डिग्री का अंतर है, फिर भी उनके संबंध में दी जाने वाली सजा को वर्गीकृत करने के उद्देश्य से उन्हें वर्गीकृत किया जा सकता है विभिन्न छोटी श्रेणियाँ जैसा कि भारतीय दंड संहिता द्वारा किया गया है। इसी प्रकार, संविधान ने, अनुच्छेद 19 (1) में उल्लिखित मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने वाले अनुमेय कानून के लिए अलग-अलग मानदंड तैयार करते हुए, सार्वजनिक व्यवस्था के खिलाफ उन अपराधों को एक अलग श्रेणी में रखा है, जिनका उद्देश्य राज्य की सुरक्षा को कमजोर करना या उखाड़ फेंकना है। इसे, और उनकी रोकथाम को विधायी संक्षिप्तीकरण का एकमात्र औचित्य बना दिया। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी, राज्य की नींव को खतरे में डालने या इसे उखाड़ फेंकने की धमकी देने के अलावा कुछ भी भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकारों में कटौती को उचित नहीं ठहरा सकता है, जबकि शांतिपूर्ण सभा का अधिकार "उप-खंड (बी)" है। "और एसोसिएशन का अधिकार" उप-खंड (सी) "" सार्वजनिक व्यवस्था "के हित में अनुच्छेद 19 के खंड (3) और (4) के तहत प्रतिबंधित किया जा सकता है, जिसमें उन खंडों में राज्य की सुरक्षा शामिल है। यह अंतर सातवीं अनुसूची की सूची III (समवर्ती सूची) की प्रविष्टि 3 में भी ध्यान देने योग्य है, जो "राज्य की सुरक्षा" और "रखरखाव" को संदर्भित करता है।

यह भी ध्यान देने योग्य है कि मसौदा समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान के मसौदे के अनुच्छेद 13 (2) में आया "देशद्रोह" शब्द अनुच्छेद 19 (2) के रूप में पारित होने से पहले ही हटा दिया गया था। इस संबंध में यह याद किया जा सकता है कि संघीय न्यायालय ने निहारेंदत्त मजूमदार बनाम द किंग एम्परर (1) में राजद्रोह को परिभाषित करते हुए कहा था कि "जिन कृत्यों या शब्दों की शिकायत की गई है वे या तो अव्यवस्था भड़काने वाले होने चाहिए या ऐसे होने चाहिए जो संतुष्ट हों।" उचित व्यक्तियों ने कहा कि यह उनका इरादा या प्रवृत्ति है", लेकिन प्रिवी काउंसिल ने उस निर्णय को खारिज कर दिया और तिलक के मामले में व्यक्त दृष्टिकोण की जोरदार पुष्टि की (1) इस आशय से कि "अपराध में दूसरों को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास करना शामिल था। सरकार के प्रति भावनाएं और विद्रोह या विद्रोह, या किसी

भी प्रकार की वास्तविक गड़बड़ी, बड़ी या छोटी" राजा सम्राट बनाम सदाशिव नारायण भालेराव (') को उत्तेजित करने या उत्तेजित करने का प्रयास नहीं करना। मसौदा अनुच्छेद 13 से "देशद्रोह" शब्द का विलोपन (2), इसलिए, यह दर्शाता है कि सरकार की उसके प्रति असंतोष या बुरी भावनाओं को भड़काने वाली आलोचना को अभिव्यक्ति और प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक उचित आधार के रूप में नहीं माना जाना चाहिए, जब तक कि यह ऐसा न हो कि यह सुरक्षा को कमजोर करता हो या ऐसा न करता हो। राज्य को उखाड़ फेंकने के लिए. यह भी महत्वपूर्ण है कि "सार्वजनिक व्यवस्था या राज्य के अधिकार को कमजोर करने" के संबंधित आयरिश फार्मूले [आयर के संविधान, 1937 के अनुच्छेद 40 (6) (i)] को स्पष्ट रूप से भारतीय संविधान के निर्माताओं का समर्थन नहीं मिला। . इस प्रकार, स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के अधिकार के अनुमेय विधायी कटौती के लिए बहुत ही संकीर्ण और कठोर सीमाएं निर्धारित की गई हैं, और यह निस्संदेह इस अहसास के कारण था कि बोलने और प्रेस की स्वतंत्रता सभी लोकतांत्रिक संगठनों की नींव में निहित है, बिना इसके निःशुल्क राजनीतिक चर्चा, कोई सार्वजनिक शिक्षा, जो लोकप्रिय सरकार की प्रक्रियाओं के समुचित कार्य के लिए अत्यंत आवश्यक है, संभव नहीं है। ऐसे आयाम की स्वतंत्रता में दुरुपयोग के जोखिम शामिल हो सकते हैं। लेकिन संविधान के निर्माताओं ने, मैडिसन के साथ, जो "संघीय संविधान के पहले संशोधन की तैयारी में अग्रणी भावना" थी, अच्छी तरह से प्रतिबिंबित किया होगा कि "इसकी कुछ हानिकारक शाखाओं को उनके विलासितापूर्ण विकास के लिए छोड़ देना बेहतर है, उचित फल देने वालों की शक्ति को घायल करने के लिए, उन्हें काट-छांट कर दूर करने की तुलना में": [निकट बनाम मिनेसोटा (') में उद्धृत]।

इसलिए हमारी राय है कि जब तक बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने वाला कोई कानून केवल राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने या उसे उखाड़ फेंकने के खिलाफ नहीं है, तब तक ऐसा कानून अनुच्छेद 19 के खंड (2) के तहत आरक्षण के अंतर्गत नहीं आ सकता है, हालांकि जो प्रतिबंध वह लगाना चाहता है, उनकी कल्पना आम तौर पर सार्वजनिक व्यवस्था के हित में की गई होगी। यह इस प्रकार है कि धारा 9 (1-ए) जो सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने या सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के व्यापक उद्देश्य के लिए प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करती है, खंड (2) के तहत अधिकृत प्रतिबंधों के दायरे से बाहर है, और इसलिए शून्य और असंवैधानिक है।

हालाँकि, यह तर्क दिया गया कि धारा 9 (1-ए) को पूरी तरह से शून्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 13 (1) के तहत, मौलिक अधिकार के साथ असंगत एक

मौजूदा कानून केवल असंगतता की सीमा तक शून्य है, इससे अधिक नहीं . • जहां तक सार्वजनिक सुरक्षा की सुरक्षा या सार्वजनिक व्यवस्था के रखरखाव में राज्य की सुरक्षा शामिल होगी, बाद के उद्देश्य के लिए लागू किया गया प्रावधान, अनुच्छेद 19 के खंड (2) द्वारा कवर किया गया था और इसे अवश्य ही शामिल किया जाना चाहिए कहा गया था, वैध माना जाएगा। हम इस विवाद को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। 'जहां एक कानून भाषा में मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाने को अधिकृत करने का इरादा रखता है, जो ऐसे अधिकार को प्रभावित करने वाली संवैधानिक रूप से अनुमत विधायी कार्रवाई के दायरे के भीतर और बाहर दोनों तरह के प्रतिबंधों को कवर करता है, वहां तक इसे बरकरार रखना संभव नहीं है। इसे संवैधानिक सीमाओं के भीतर लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अलग करने योग्य नहीं है। जब तक इसे संविधान द्वारा अनुमोदित नहीं किए गए उद्देश्यों के लिए लागू किए जाने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, तब तक इसे पूरी तरह से असंवैधानिक और शून्य माना जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, अनुच्छेद 19 का खंड (2) केवल उन मामलों में भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति देता है, जहां राज्य के लिए खतरा शामिल है, एक अधिनियम, जो उन मामलों में लागू होने में सक्षम है जहां ऐसा कोई खतरा उत्पन्न नहीं हो सकता, किसी भी सीमा तक संवैधानिक एवं वैध नहीं माना जा सकता।

इसलिए आवेदन की अनुमति दी जाती है और मद्रास राज्य में याचिकाकर्ता की पत्रिका के प्रवेश और प्रसार पर रोक लगाने वाले उत्तरदाताओं के आदेश को रद्द कर दिया जाता है।

एफएजेडएल अली जे.-बृज भूषण और अन्य बनाम द स्टेट(टी) में मेरे द्वारा दिए गए कारणों के लिए, जो व्यावहारिक रूप से।

इसमें वही प्रश्न शामिल है जो इस मामले में शामिल है। मेरा मानना है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई राहत नहीं दी जा सकती। इस दृष्टि से, मैं इस याचिका को खारिज कर दूंगा, लेकिन मैंने दूसरे मामले में जो कहा है, उसके पूरक के रूप में मुझे कुछ टिप्पणियां जोड़नी चाहिए।

मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि अंतिम विश्लेषण में इस मामले में तय किया जाने वाला वास्तविक प्रश्न यह है कि क्या "प्रांत की शांति और शांति के लिए खतरा पैदा करने वाली अव्यवस्थाएं" और "सार्वजनिक सुरक्षा" का उल्लंघन एक ऐसा मामला होगा जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है। या नहीं। मैंने अधिनियम की प्रस्तावना से उल्टे अल्पविराम के भीतर उद्धृत शब्दों को उधार लिया है जो इसके दायरे और आवश्यकता

को दर्शाता है और अधिनियम की वैधता पर हमला करने वाले हमारे सामने उठाए गए प्रश्न को मेरे द्वारा सुझाए गए तरीके से तैयार किया जाना चाहिए। यदि प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, जैसा कि मुझे लगता है कि यह होना चाहिए, तो लागू कानून सार्वजनिक सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए "किसी भी दस्तावेज़ या दस्तावेजों के वर्ग" के मद्रास राज्य में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाता है। संविधान के अनुच्छेद 19(2) में निर्धारित आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। हमें संबोधित तर्कों की प्रवृत्ति से, ऐसा प्रतीत होता है कि यदि कोई दस्तावेज़ देशद्रोही है, तो उसके प्रवेश को वैध रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, क्योंकि देशद्रोह एक ऐसा मामला है जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करता है; लेकिन, दूसरी ओर, अगर दस्तावेज़ की गणना सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने और सार्वजनिक सुरक्षा को प्रभावित करने के लिए की जाती है, तो इसके प्रवेश को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि सार्वजनिक अव्यवस्था और सार्वजनिक शांति में गड़बड़ी ऐसे मामले नहीं हैं जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करते हैं। अपनी बात करूं तो मैं इस तर्क को समझ नहीं पा रहा हूं। बृज भूषण और अन्य बनाम राज्य (1) में, मैंने यह दिखाने के लिए अच्छे अधिकार उद्धृत किए हैं कि राजद्रोह की गंभीरता विकार पैदा करने की प्रवृत्ति के कारण होती है और सर जेम्स स्टीफन जैसे आपराधिक कानून के अधिकारी ने राजद्रोह को सार्वजनिक शांति के खिलाफ अपराध के रूप में वर्गीकृत किया है। . यदि हां, तो राजद्रोह ऐसा मामला कैसे हो सकता है जो राज्य की सुरक्षा को कमजोर करेगा और सार्वजनिक अव्यवस्था और सार्वजनिक सुरक्षा में गड़बड़ी ऐसा मामला नहीं होगा? यह तर्क दिया गया था कि एक छोटा सा दंगा या झगड़ा राज्य की सुरक्षा को कमजोर नहीं करेगा, लेकिन इस तर्क का दोतरफा उत्तर है:-

(1) अधिनियम, जैसा कि इसकी प्रस्तावना से पता चलता है, छोटे विकारों के लिए नहीं बल्कि प्रांत की शांति और शांति के लिए खतरा पैदा करने वाले विकारों के लिए है, (2) राजद्रोह के अपराध में गंभीरता के कुछ अंश भी हैं एक तुच्छ व्यक्ति द्वारा हल्के से देशद्रोही चरित्र का लेखन, आम आदमी के दृष्टिकोण से, राज्य की सुरक्षा को कमजोर करने वाला मामला नहीं हो सकता है, लेकिन यह उस कानून को प्रभावित नहीं करेगा जिसका उद्देश्य देशद्रोह की जाँच करना है। यह भी कहा गया कि कानून जिस स्थिति में है, उसका राज्य कार्यपालिका द्वारा दुरुपयोग किया जा सकता है, लेकिन कानून का दुरुपयोग एक बात है और उसका असंवैधानिक होना दूसरी बात है। हम यहां केवल बाद वाले पहलू से चिंतित हैं। मैं इस मामले को आगे नहीं बढ़ाऊंगा क्योंकि मैंने संबंधित मामले में इस विषय पर काफी कुछ कहा है।

याचिका मंजूर.

याचिकाकर्ता के लिए एजेंट:-*के. एल गोभी।*
विपरीत पक्ष के लिए एजेंट:-. *ए मेहता.*

चन्द्र कान्त शुक्ल की देखरेख में शशि प्रभा द्वारा अनुवादित